>

Title: The Speaker, on behalf of the House, congratulated Shri Ravi Kumar Dahiya for winning Silver Medal in Wrestling in the ongoing Tokyo Olympics.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री रवि कुमार दहिया ने ओलम्पिक खेलों में 57 किलोग्राम कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है । इन खेलों में भारत का पांचवां पदक है । 23 वर्षीय रवि कुमार दहिया ने यह उपलब्धि अपने पहले ही ओलम्पिक खेलों में हासिल की है । मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री रवि कुमार दहिया को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं । मेरी आशा है कि उनकी इस उपलब्धि से देश के सभी युवाओं को अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी ।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 261, श्री सुनील कुमार सिंह ।

… (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra, Adv. A. M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

(Q. 261)

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 तक कुल संस्थागत प्रसव में हॉस्पिटलों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से कम थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2019-20 तक लगभग 95 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । सरकार इस लक्ष्य को 100 परसेंट करने के लिए प्रयास कर रही है । ... (व्यवधान) इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना सहित अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । ... (व्यवधान)

इसके साथ ही जो मैंने प्रश्न पूछा है, उसके विस्तृत जवाब के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सुविधा केन्द्रों की संख्या मात्र 253 है । मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में 6, लातेहार में 7 और पलामू में मात्र 10 सुविधा केन्द्र हैं । ... (व्यवधान) झारखंड की स्थिति अत्यंत खराब इस दृष्टि से भी है कि वहां पिछले दो-ढ़ाई सालों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नये प्रसति केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक केंद्र खोलने की कोई योजना है? ... (व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए पूछे गए प्रश्नों का रिप्लाई एमओएस डॉ. भारती पवार दे रही हैं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. भारती पवार एक आदिवासी समाज से आती हैं । ... (व्यवधान) आदिवासी महिला हैं। उन्होंने एमबीबीएस तक पढ़ाई की है । ...

(व्यवधान) कांस्टीट्युशन ने महिलाओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाया है । माननीय मोदी जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है और आज वह पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिप्लाई करने के लिए खड़ी हुई हैं । ... (व्यवधान) लेकिन आज विपक्ष द्वारा एक आदिवासी महिला, जो देश और संसद में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रश्नों का रिप्लाई देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते हैं । ... (व्यवधान) एक महिला का, आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है । ... (व्यवधान)

मेरी आपसे प्रार्थना है कि विपक्ष को कहें, ... (व्यवधान) मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि एक आदिवासी महिला को सुनें । ... (व्यवधान) एक पढ़ी लिखी आदिवासी महिला का रिप्लाई कृपया करके सुनें । ... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में महिला मंत्री होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारे देश की महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहें, इस प्रयास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, शायद उसे सुनने की भावना विपक्ष में नहीं है । ... (व्यवधान) उनमें हिम्मत भी नहीं है कि हमारी तरफ की सुनें ।... (व्यवधान) महिलाएं सुरक्षित रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मातृत्व योजना को अनेक योजनाओं के साथ इतने बड़े पैमाने पर लाए हैं । ... (व्यवधान) मुझे लगता है, जैसे माननीय मंत्री मनसुख भाई जी ने कहा, उन्हें यह भी सुनना पड़ेगा । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वर्ष 2014-15 से पहले 122 था यानी 122 महिलाओं की मृत्यु प्रति एक लाख लाइव्स पर होती थी, आज वह कम होकर, डिक्लाइन होकर 113 हो गई है । यह एक बड़ी पहल है । ... (व्यवधान) हमारी मातृत्व शक्ति सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें ।... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, पीएसएमए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो योजना बनाई गई है, जिसमें हर महीने की 9 तारीख को मातृत्व का आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रैकिंग हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखने की सुविधा

मिले । ... (व्यवधान) झारखंड के लिए सुविधा मिली है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होकर 165 से 71 हुआ है । ... (व्यवधान) हमारी सरकार मातृत्व के लिए कटिबद्ध है, मातृत्व सुरक्षित है ।... (व्यवधान)

आज मैं वही दोहराना चाहूंगी कि देश की किसी भी शक्ति के लिए, मातृत्व के लिए हमें कोई नहीं रोकेगा, मैं यहां बड़े दुख के साथ कह रही हूं कि यह भी सुनने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है । ... (व्यवधान) मातृत्व योजना के साथ खड़े रहिए । ... (व्यवधान) हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें ।... (व्यवधान) झारखंड के लिए सरकार कटिबद्ध है । माननीय सदस्य ने पूछा है, हम चतरा, लातेहार और पलामू में जरूर केंद्र बढ़ाएंगे और वहां की राज्य सरकार से भी बात करेंगे । धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 262 और 279 क्लब किया जाता है ।

श्री जयदेव गल्ला जी ।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 262 and 279)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में और विशेष रूप

से हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नैचुरल डिजॉस्टर हो रहे हैं । इसके लिए जो कारण हैं, क्या मंत्रालय द्वारा उनके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई है? ... (व्यवधान) इसके साथ-साथ रिसेंटली लद्दाख पॉर्लियामेंटरी कांस्टिट्यूएंसी में ज्यादातर कारगिल के अलग-अलग क्षेत्रों में और लेह के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ है? ... (व्यवधान) जिन लोगों के घर बह गए हैं, खेती में नुकसान हुआ है और माल-मवेशी बह गए हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लामेट चेंज की ओर से कौन-सी योजनाएं चल रही हैं और कौन-से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं । ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । ... (व्यवधान) यह महत्वपूर्ण प्रश्न क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। आज के समय में जो क्लाइमेंट चेंज का विषय है, निश्चित रूप से वह प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। हम यह मानते हैं कि क्लामेंट चेंज सामाजिक-आर्थिक और जो बॉयो डायवर्सिटी है, उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है । आपने अपना प्रश्न विशेष रूप से हिमालय के संबंध में पूछा है । ... (व्यवधान) सरकार द्वारा हिमालय क्षेत्र में नेचर लर्निंग सैंटर्स की व्यवस्था की जा रही है ।

दूसरा, हिमालय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment द्वारा Integrated Ecodevelopment Research Programme सरकार द्वारा किया जाता है । ... (व्यवधान) उसके अतिरिक्त हिमालयन क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा Environment education awareness and training का प्रोग्राम चलाया जाता है । इसके अलावा मिनिस्ट्री द्वारा नियमित रूप से जितने भी जलवायु परितर्वन के विषय हैं, उनके अध्ययन के लिए Environmental Information System Scheme बनाई जाती है । भारत में The National Museum of Natural History और उसके जो रीजनल सैंटर्स हैं, उनके द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऐस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है । ... (व्यवधान) Under the National Mission for Sustaining Himalayan

Ecosystem द्वारा हिमालयन क्षेत्र के जो 12 राज्य हैं, वहां भी विशेष अध्ययन और विशेष संरक्षण के लिए कार्य किये जा रहे हैं । … (व्यवधान)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे सप्लीमेंट्री प्रश्न में जानना चाहूंगा कि नेचर लर्निंग सैंटर्स और G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment जैसे अच्छे इंस्टिट्यूट्स के माध्यम से लद्दाख और खासकर जो हिलालय के टॉप पर रहते हैं और वहां के वातारण में जो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को, गांव कहां बसना चाहिए, घर कहां बनना चाहिए या कहां नहीं बनना चाहिए, इन चीजों के बारे में इन इंस्टिट्यूट्स द्वारा कितने अवेयरनेस कैंपेन किए गए? … (व्यवधान) इसके लिए आगे कौन-सी पॉलिसी बनाने की योजना है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, लद्दाख भारत में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है । लद्दाख का जो फ्लोरा और फौना है और लद्दाख में जिस प्रकार से पर्यावरण संतुलन का विषय है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है । … (व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस बात पर पूरी तरह से चिंता व्यक्त कर रहे हैं । वे लद्दाख की वाइल्ड लाइफ कमेटी के मेम्बर हैं । अभी 24 जुलाई को उस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसको उन्होंने अटेंड भी किया है । उसमें सारे संरक्षणीय विषयों का और लद्दाख के फ्लोरा और फौना जैसे विषयों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है । … (व्यवधान) हिमालयन साइंस इंस्टिट्यूट द्वारा विशेष रूप से लद्दाख को लेकर जो योजना है, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जयदेव गल्ला जी – उपस्थित नहीं ।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH: Sir, my question is about the impact of illegal mining on our surroundings. Heavy duty explosives

and chemicals are used for the blast, and there is rising incidence of respiratory disorders, lung disorders, and other health issues that villages and its surrounding areas are facing.

Also, ground water table, air quality and crops are affected. Livestock are not able to graze because of the accumulation of chemical dust in these areas. ....*(Interruptions)*

My question to the Government is whether the Government is taking any measures to prevent illegal mining and protect the environment. Has the Government developed any mechanism to resolve such challenges in our villages? ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें, तो वह जवाब दे सकते हैं । आप माननीय सदस्या को बाद में भी बता सकते हैं ।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में एक जनरल बात पूछी है । …(व्यवधान) मैं उनको बताना चाहूंगा कि देश में जो एयर पॉल्यूशन है, उसके लिए हमने पूरे देश के 34 राज्यों में 1,114 मॉनीटरिंग स्टेशन्स की व्यवस्था की है । …(व्यवधान) उनके क्षेत्र के संबंध में एन्वॉयरमेंट के एयर पॉल्यूशन के जो मॉनीटरिंग सैंटर्स हैं, वे उसकी जानकारी मुझसे ले सकती हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 263, श्रीमती साजदा अहमद ।

… (व्यवधान)

(Q. 263)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत

और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 264, श्री ए. के. पी. चिनराज ।

… (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 264)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 265, श्रीमती भावना गवली (पाटील) ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम पवन राजेनिंबालकर ।

… (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 265)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 266, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी ।

… (<u>व्यवधान</u>)

(Q.266)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI : Sir, there are over nine lakh children facing severe malnutrition in India. To address this problem, the

Odisha Government is taking several measures. ....*(Interruptions)* Odisha supports the nutrition agenda through agricultural policies, public distribution system, and others. Odisha has become the first Indian State to draw a nutrition budget in the country. UNICEF as well as NITI Aayog have appreciated the efforts of the Government of Odisha in the direction of addressing malnutrition problem. .... *(Interruptions)*

In the 2021-22 Budget, the Union Government merged the Supplementary Nutrition Programme and Poshan Abhiyan. But the Budget Estimate on nutrition has gone down to Rs.2700 crore in 2021-22 from Rs.3700 crore in 2020-21. Budget enhancement is required if you want to sustain the momentum of the Mission. ....*(Interruptions)*

Sir, I would like to ask the hon. Minister whether there is any proposal to increase the allocation of budget in terms of nutrition and thereby provide support to States like Odisha, where this programme is running successfully. ....*(Interruptions)*

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, through you, I would like to bring to the attention of the hon. Member that the Government of India under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi is committed to ensure that the nutritional needs of all children, pregnant and lactating women are met. ....*(Interruptions)*

So far as the expression of the hon. Member about reduction in budget is concerned, on an earlier occasion, I, along with the Minister of State in the Ministry of Women and Child Development have replied in this very august House that given the revised expenditure of our Ministry, we have ensured that not a penny is spent less on the nutritional needs of all States, including the State of Odisha. We are in

continuous engagement with the State Government of Odisha to ascertain the infrastructural and nutritional needs of the project. .... *(Interruptions)*

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: Sir, Mission Poshan basically addresses the problem of Aspirational Districts. What steps are being taken to address this issue in the districts which are not in the category of Aspirational Districts? ....*(Interruptions)*

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I think the anomaly that has been expressed by the hon. Member needs to be corrected. Poshan Abhiyan is an effort of the Government of India across all districts and all States of our country. Before the Modi Government, there had been Governments, which had not given instruments in the anganwadi centres so that a child could be measured or weighed. ....*(Interruptions)* I am very happy to express on the floor of this august House that for the first time in the history of independent India the hon. Prime Minister under the Poshan Abhiyan has ensured that not only the measuring devices are given to anganwadi centres but also every anganwadi centre is covered with smart phone so that data can be automatically generated in terms of both beneficiaries, that need to get enrolled, and the benefits, that are to be approved to them. ....*(Interruptions)*

Sir, in the month of March, Poshan Tracker was launched by this very Government and I am happy to say that in just three months we have had every anganwadi in the country now digitally connected with the Government of India so that the needs of the anganwadi centres including challenges are met with solutions. ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 267, श्री गौरव गोगोई ।

... (व्यवधान)